

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 28, शुक्रवार, शाके 1946-जुलाई 19, 2024 Asadha 28, Friday, Saka 1946- July 19, 2024	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, July 19, 2024

No. F. 2(32)Vidhi/2/2022.- The following Act of the Rajasthan State Legislature received the assent of the President on the 5th day of July, 2024 and is hereby published for general information:-

**THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS (AMENDMENT)
ACT, 2022**

(Act No. 4 of 2024)

(Received the assent of the President on the 5th day of July, 2024)

An

Act

further to amend the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-third Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Agricultural Produce Markets (Amendment) Act, 2022.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 17, Rajasthan Act No. 38 of 1961.- In section 17 of the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Act No. 38 of 1961), hereinafter in this Act referred to as the principal Act, for the existing expression “physical boundaries of principal market yards, sub-market yards and market sub-yards managed and run by the market committees formed and, private market yards, private market sub-yards, direct marketing collection centres, and private farmer-consumer market yards managed by persons holding licences or, any warehouses, silos, cold storages or other structures notified as markets or deemed markets, under this Act,”, the expression “market area” shall be substituted.

3. Amendment of section 17-A, Rajasthan Act No. 38 of 1961.- In sub-section (1) of section 17-A of the principal Act, for the existing expression “physical boundaries of

principal market yards, sub-market yards and market sub-yards managed and run by the market committees formed and, private market yards, private market sub-yards, direct marketing collection centres, and private farmer-consumer market yards managed by persons holding licenses or, any warehouses, silos, cold storages or other structures notified as markets or deemed markets, under this Act,”, the expression “market area” shall be substituted.

4. Insertion of new section 17-B, Rajasthan Act No. 38 of 1961.- After the existing section 17-A and before the existing section 18 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

“17-B. Power to collect user charge.- The market committee shall collect user charge from the licensees in the prescribed manner on non-notified agricultural produce and food products brought or bought or sold by them in the market yards and sub-market yards established under this Act, at such rate as may be specified by the State Government by notification in the Official Gazette.”.

ब्रजेन्द्र कुमार जैन,

Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(गुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 19, 2024

संख्या प.2(32)विधि/2/2022.- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2022 (एक्ट नं. 4 ऑफ 2024)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2022

(2024 का अधिनियम संख्यांक 4)

(राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 5 जुलाई, 2024 को प्राप्त हुई)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1961 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 की धारा 17 का संशोधन.- राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 38), जिसे इस अधिनियम में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 17 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "इस अधिनियम के अधीन, गठित की गयी मण्डी समितियों द्वारा प्रबंधित और चलाये गये प्रधान मण्डी यार्ड, उप-मण्डी यार्ड और मण्डी उप-यार्ड की भौतिक सीमाओं में,

और अनुज्ञप्तिधारी व्यक्तियों द्वारा प्रबंधित निजी मण्डी यार्ड, निजी मण्डी उप-यार्ड, प्रत्यक्ष विपणन संग्रहण केन्द्रों और निजी कृषक-उपभोक्ता मण्डी यार्ड में, या मण्डियों या मानित मण्डियों के रूप में अधिसूचित किन्हीं भाण्डागारों, कोष्ठागारों, शीतागारों या अन्य संरचनाओं में, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उनके द्वारा मण्डी क्षेत्र में" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 1961 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 की धारा 17-क का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 17-क की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "इस अधिनियम के अधीन, गठित की गयी मण्डी समितियों द्वारा प्रबंधित और चलाये गये प्रधान मण्डी यार्ड, उप-मण्डी यार्ड और मण्डी उप-यार्ड की भौतिक सीमाओं में, और अनुज्ञप्तिधारी व्यक्तियों द्वारा प्रबंधित निजी मण्डी यार्ड, निजी मण्डी उप-यार्ड, प्रत्यक्ष विपणन संग्रहण केन्द्रों और निजी कृषक-उपभोक्ता मण्डी यार्ड में, या मण्डियों या मानित मण्डियों के रूप में अधिसूचित किन्हीं भाण्डागारों, कोष्ठागारों, शीतागारों या अन्य संरचनाओं में, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उनके द्वारा मण्डी क्षेत्र में" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 1961 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 में नयी धारा 17-ख का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 17-क के पश्चात् और विद्यमान धारा 18 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"17-ख. उपयोक्ता प्रभार संगृहीत करने की शक्ति.- मण्डी समिति, अनुज्ञप्तिधारियों से, इस अधिनियम के अधीन, गठित मण्डी यार्ड और उप-मण्डी यार्ड में उनके द्वारा लायी गयी या क्रीत या विक्रीत गैर-अधिसूचित कृषि उपज और खाद्य उत्पादों पर ऐसी दर से, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, विहित रीति से उपयोक्ता प्रभार संगृहीत करेगी।"

ब्रजेन्द्र कुमार जैन,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।